

मुख्य समाचार

- केन्द्र सरकार ने हर वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का किया फैसला, अधिसूचना जारी।
- चुनाव आयोग ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने का दिया निर्देश, हाउसिंग सोसाइटी में भी मतदान केन्द्र बनाने को कहा।
- झारखंड हाईकोर्ट ने नियुक्ति नियमावली को चुनाती देने वाली याचिका खारिज की, पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति का रास्ता साफ।
- राज्य भर में आज होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, लगभग 10 लाख मामलों के निष्पादन का लक्ष्य।
- मौसम विभाग ने आज रांची, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम समेत कई जिलों में तेज बारिश का जताया पूर्वानुमान, वज्रपात की भी चेतावनी जारी।

\*\*\*\*\*

केन्द्र सरकार ने प्रति वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1975 में देश में आपातकाल लगाया था। इस सिलसिले में सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि जनता 25 जून 1975 की रात कभी नहीं भूल सकती, जब संविधान की हत्या की गई थी।

\*\*\*\*\*

भारत निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव अरविन्द आनंद और रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने शहरी मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शहरी क्षेत्रों में जिन हाउसिंग सोसाइटी में तीन सौ से अधिक मतदाता हैं, वहां मतदान केन्द्र बनाया जायेगा। इस मौके पर प्रधान सचिव श्री आनंद ने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण त्रुटि रहित होने से ही मतदान प्रतिशत बेहतर होगा।

\*\*\*\*\*

निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव अरविन्द आनंद के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम ने कल जमशेदपुर का दौरा किया। इस दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर प्रधान सचिव श्री आनंद ने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण त्रुटि रहित होने से ही मतदान प्रतिशत बेहतर होगा।

\*\*\*\*\*

राज्य में पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इनकी नियुक्ति के लिए बनी नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका कल झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने तेईस सौ तेरासी पदों पर नियुक्ति के लिए वर्ष 2023 में विज्ञापन जारी किया था। प्रार्थी ने नियमावली की कुछ शर्तों को असंवैधानिक बताते हुए अदालत से नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने का आग्रह किया था। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह याचिका खारिज कर दी।

\*\*\*\*\*

केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही लखपति दीदी योजना ने महिलाओं में काम करने की ललक बढ़ायी है।

\*\*\*\*\*

आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी  
वेबसाइट [news on air.gov.in](http://news.on.air.gov.in) पर लॉग ऑन कर सकते हैं।

ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR news alerts और फेसबुक पेज All India Radio news पर भी  
उपलब्ध है।

आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल

@AIR news अंडर स्कोर\_ranchi

और

फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा

YOUTUBE Channel AIR NEWS Ranchi

पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।

\*\*\*\*\*

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार—झालसा की ओर से आज राज्यभर की अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इसमें 10 लाख मामलों के निष्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामलों के निष्पादन के लिए उच्च न्यायालय में दो खंडपीठों का गठन किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्घाटन के बाद झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विद्युत रंजन षाड़गी और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद उच्च न्यायालय और रांची सिविल कोर्ट में लोक अदालत के लिए बनाई गई खंडपीठों का निरीक्षण करेंगे।

\*\*\*\*\*

राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री डा. इरफान अंसारी ने संताल परगना में डेमोग्राफी बदलने के भाजपा के आरोपों पर पलटवार किया है। एक केस के सिलसिले में दुमका पहुंचे डा. अंसारी ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर कहा कि इसके लिए जिम्मेवार राज्य सरकार नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार है।

\*\*\*\*\*

नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स के समग्र स्कोर में पिछली बार की तुलना में झारखंड के स्कोर में सुधार हुआ है, लेकिन सतत विकास लक्ष्य पाने के मामले में इसका प्रदर्शन निराशाजनक है। राज्यों की सूची में झारखंड का स्थान नीचे से दूसरे नम्बर पर है। हालांकि झारखंड परफार्मर राज्यों की श्रेणी में शामिल है। 2021 की रिपोर्ट में झारखंड का स्कोर 56 था जो बढ़कर 62 हो गया है।

\*\*\*\*\*

नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023—24 जारी किया है और कहा कि वैश्विक प्रतिकूलताओं के बावजूद भारत सतत विकास लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहा है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स सतत विकास लक्ष्यों पर राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय प्रगति को मापने के लिए देश का प्रमुख उपकरण है। सूचकांक को नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम और अन्य लोगों की उपस्थिति में लॉन्च किया था। यह प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के लिए 16 एसडीजी पर लक्ष्य—वार स्कोर की गणना करता है।

\*\*\*\*\*

राज्य में मानसून फिर से सक्रिय है। रांची सहित राज्य के कई जिलों में कल रात भी बारिश हुई। मौसम विज्ञान केन्द्र रांची ने आज रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा, सरायकेला—खरसावा, गुमला समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान वज्रपात की भी संभावना व्यक्त की गयी है। 18 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है।

\*\*\*\*\*

भारत और जिम्बाब्वे के बीच चौथा टी-ट्वेंटी क्रिकेट मैच आज हरारे में खेला जाएगा। पांच मैचों की श्रृंखला में भारत दो-एक से आगे है। शुभमान गिल के नेतृत्व में पहले मैच में भारत को जिम्बाब्वे से 13 रन से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद भारत ने अगले दोनों मैच जीतकर श्रृंखला में दो-एक की बढ़त ले ली थी। दूसरे मैच में भारत ने मेजबान टीम को सौ रन से करारी शिकस्त दी थी। वहीं, तीसरे मैच में जिम्बाब्वे 23 रन से हार गया था। श्रृंखला का पांचवां और अंतिम मैच हरारे में ही कल खेला जाएगा।

\*\*\*\*\*

### अखबारों की सुर्खियां

राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 15 सौ पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिये जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है।

हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है झारखंड में निजी जैसे बन रहे सरकारी स्कूल।

दैनिक भास्कर के शब्द हैं- ईडी ने जयकुमार से पूछा-एनआईसी में रिकॉर्ड में छेड़छाड़ क्यों की, नहीं दिया जवाब।

प्रभात खबर ने लिखा है- हाउसिंग सोसाइटी में भी बनेंगे मतदान केन्द्र।

दैनिक जागरण की सुर्खी है- संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जायेगा 25 जून।

अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनायी है।

\*\*\*\*\*